**International Journal of Sociology and Political Science**
**www.sociologyjournal.in**
**Online ISSN: 2664-7745, Print ISSN: 2664-7737**
**Received: 07-10-2022, Accepted: 06-11-2022, Published: 21-11-2022**
**Volume 4, Issue 2, 2022, Page No. 104-107**

# भारत बांग्लादेश संबंधः एक अध्ययन

**डॉ. पुष्पा देवांगन**
प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र, के. पी. महाविद्यालय, बंधापाली सारंगढ़, छत्तीसगढ़, भारत

**सारांश**
बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसकी नींव के निर्माण में भारत ने एक कुशल राजगीर की भूमिका अदा की है। इसके साथ भारत की भू–भागीय सीमाएँ 4096 कि.मी. के आस–पास हैं जो भारत के पड़ोसी देशों की सीमाओं में सबसे लंबी है। भारत और बांग्लादेश के संबंध सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक एवं आर्थिक आदि कई स्तरों पर एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक साझा इतिहास, एक साझी विरासत, भाषा व संस्कृति का मेल, साहित्य, संगीत और कला, स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष और मुक्ति की साझी विरासत दोनों देशों को एक सूत्र में बांधते हैं। दोनों देश एक–दूसरे की अंतरंग भावनाओं को भ्रातृत्व भाव से अनुभव करते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण दक्षिण एशिया के सबसे बड़े देश भारत और दक्षिण एशिया के उभरते टाइगर की उपमा हासिल करने वाले बांग्लादेश के आपसी संबंध अपना अलग स्थान रखते हैं। इसमें परंपरागत पड़ोसी की भाँति कुछ विवाद भी हैं तो आपसी सहयोग व विश्वास की मजबूत इमारत भी मौजूद है।

**मुख्य शब्दः** भारत, बांग्लादेश, संबंध, मुद्दे, सहयोग

बांग्लादेश का एक देश के रूप में उदय दिसंबर 1971 में भारत– पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की पराजय का परिणाम था। यह युद्ध पाकिस्तान के क्रूर व आतंकपूर्ण शासन के विरुद्ध बांग्लादेशी विद्रोह का चरमोत्कर्ष था। तेरह दिन के भारत–पाक युद्ध के बाद 16 दिसंबर, 1971 को पाकिस्तान ने अपनी पराजय स्वीकारते हुए आत्मसमर्पण कर दिया जिससे पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में अभ्युदय हुआ। एक तरफ बांग्लादेश की जनता के लिये यह आतंक, क्रूरता व यातना का अंत और देश के स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा थी, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिये यह लोकतांत्रिक समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की विजय थी। (चौधरी, जीडब्ल्यू 2019) [1]

बांग्लादेश के उदय होने पर उसके राष्ट्रनायक शेख मुजीबुर्रहमान देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 16 से 18 फरवरी, 1972 को भारत की आधिकारिक यात्रा की जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ उनकी वार्त्ता के बाद यह घोषणा की गई कि भारत–बांग्लादेश संबंध लोकतंत्र, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता आदि के सिद्धांतों पर आधारित होंगे। इसके साथ ही दोनों देश जातिवाद व उपनिवेशवाद के सभी रूपों का विरोध करेंगे।

मुजीबुर्रहमान का बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र था। इस अवधि में बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध बहुत मधुर रहे जिसमें दोनों देशों ने परस्पर हितों की पूर्ति हेतु व विकास को गति देने हेतु कई समझौते किये, किंतु 15 अगस्त, 1975 को बांग्लादेशी सेना के कुछ मध्यस्तरीय सैनिकों ने एक सैन्य विद्रोह करके मुजीबुर्रहमान तथा उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी। हालाँकि इस हत्याकांड में मुजीबुर्रहमान की पुत्री शेख हसीना पढ़ाई के सिलसिले में उस समय भारत में होने के कारण बच गई जो आज बांग्लादेश का सफल नेतृत्व कर रही हैं।

बंग बंधु मुजीबुर्रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश में स्थापित हुए जियाउर्रहमान के सैनिक शासन में धार्मिक कट्टरता तेजी से बढ़ी और वहाँ भारत विरोधी ताकतें मजबूत होने लगीं जिससे दोनों देशों के संबंध कटु हो गए। वर्ष 1981 में जियाउर्रहमान की भी हत्या हो गई। उसके बाद शासन करने वाले उसके उत्तराधिकारी के विरुद्ध एक रक्तहीन क्रांति हुई जिसके फलस्वरूप लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद सत्ता में आए। इरशाद के समय भी भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध अच्छे नहीं रहे। उनके उपरांत बेगम खालिदा जिया सत्ता में आईं। उनके सत्ता में आने के बाद भारत के साथ फिर से सामान्य संबंध आरंभ हुए, खालिदा जिया के बाद जब शेख हसीना सत्ता में आईं तो यह सामान्य प्रक्रिया विशिष्ट संबंधों की स्थापना में परिवर्तित हो गई। (कुमार, आर. 2017) [4]

## दोनों देशों के मध्य विवादित मुद्दे

भारत व बांग्लादेश के बीच के रिश्ते की यह विशेषता रही है कि इसमें समय–समय पर नरमी– गरमी आती रहती है, किंतु कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिनमें दोनों देशों के मध्य स्थायी तौर पर विवाद है। इसमें सबसे प्रमुख है गंगा नदी के पानी के बँटवारे का मुद्दा गंगोत्री से निकलने वाली गंगा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में दो धाराओं में बँट जाती है। एक धारा हुगली नदी के नाम से पश्चिम बंगाल के निचले भागों में चली जाती है, जबकि दूसरी धारा पद्मा के नाम से भारत–बांग्लादेश सीमा के साथ–साथ बहती हुई ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व यह मेघना नदी में मिल जाती है। गंगा नदी के संदर्भ में भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद का मुद्दा लगभग हर वर्ष पानी की कमी के मौसम में पानी के बँटवारे या उसका हिस्सा प्राप्त करने से संबंधित विवाद है। दरअसल मार्च से मई की अवधि में इस क्षेत्र में गंगा का प्रवाह घटकर 55,000 क्यूसेक तक आ जाता था जिसमें से कोलकाता बंदरगाह के संचालन के लिये

भारत 40 हजार क्यूसेक पानी का इस्तेमाल करता था और बांग्लादेश के लिये 15 हजार क्यूसेक पानी ही बचता था इसलिये बांग्लादेश के निर्माण के बाद से ही यह मामला वहाँ एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। भारत ने फरक्का बांध बनाकर कोलकाता बंदरगाह का सुचारु संचालन तो सुनिश्चित कर लिया किंतु इस कारण दोनों देशों के संबंध खराब शुरू हो गए। ऐसे में सबसे पहले इंदिरा–मुनोर समझौते के तहत गंगा के पानी के बँटवारे का समाधान निकाला गया। तत्पश्चात् मोरारजी की सरकार और तत्कालीन बांग्लादेशी सरकार के मध्य एक समझौता हुआ किंतु इससे यह विवाद हल नहीं हुआ। अंततः वर्ष 1996 में भारत व बांग्लादेश के बीच गंगा जल समझौता हुआ जिसमें यह भी प्रावधान किया गया कि तीस वर्ष के पश्चात् दोनों देशों की सहमति से इस समझौते का नवीनीकरण किया जा सकेगा। इस समझौते के अनुसार यदि फरक्का से पानी की आपूर्ति 70,000 क्यूसेक या उससे कम हो तब दोनों देशों को उपलब्ध पानी का पचास–पचास प्रतिशत मिलेगा। यदि जल का प्रवाह 70,000 से 75,000 क्यूसेक होगा तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक और शेष पानी भारत के पास रहेगा। यदि फरक्का से पानी का प्रवाह 75,000 क्यूसेक से अधिक होगा तो भारत 40,000 क्यूसेक अपने लिये रखकर शेष बांग्लादेश को दे देगा। (पॉल, एम., और खान, एमएच 2020) [9]

ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि भारत और बांग्लादेश के बीच छोटी–बड़ी कुल करीब 50 से अधिक नदियाँ बहती हैं, जबकि 1996 के गंगाजल समझौते की अतिरिक्त दोनों देशों में पानी के बँटवारे को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाया है, जिससे गाहे–बगाहे पानी का मुद्दा दोनों में तनाव पैदा करता रहता है।

भारत व बांग्लादेश के मध्य विवाद का दूसरा मुख्य मुद्दा अवैध प्रवासियों का मामला है। गौरतलब है कि आर्थिक पिछड़ेपन व सांप्रदायिक तनाव के कारण बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर चुके हैं। इनमें से ज्यादातर काम की तलाश में भारत आए और यहाँ की झुग्गी बस्तियों में बस गए। खासकर असम में इनकी घुसपैठ इतनी बढ़ी कि वहाँ के स्थानीय निवासियों से इनका संघर्ष होना शुरू हो गया जिसके प्रत्युत्तर में भारत सरकार को एनआरसी की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। भारत के लगभग सभी प्रदेशों में जहाँ–तहाँ बाग्लादेशी प्रवासी लंबे समय से अवैध रूप से बसे हुए हैं। पहले से ही जनसंख्या के दबाव से त्रस्त भारत के लिये यह स्थिति दिनोंदिन गंभीर बनती जा रही है। इसी संकट की कड़ी में पिछले कुछ वर्षों से रोहिंग्या शरणार्थियों का मामला भी जुड़ गया है जो म्यांमार से निकलकर बांग्लादेश होते हुए भारत में अवैध रूप से घुस रहे हैं। ये अवैध प्रवासी कई तरह की समस्याएँ पैदा कर करे हैं, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक भार पड़ना, स्थानीय निवासियों से संघर्ष, शहरी क्षेत्रों में झुग्गी बस्तियों का विस्तार, कई तरह के अपराधों में इनकी संलिप्तता, सरकारी सेवाओं तक पहुँच हेतु फर्जी राशन कार्ड, आधार कार्ड व वोटर कार्ड बनवाने जैसे अवैध कार्य इत्यादि। दोनों देशों के बीच प्राकृतिक एवं पूर्णरूपेण मानवनिर्मित सीमा नहीं होने के कारण यह समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस तरह के आवागमन को रोकने के लिये भारत ने बांग्लादेश की सीमा पर काँटेदार तार की बाड़बंदी करने का प्रस्ताव दिया था जिसे उसने स्वीकार भी किया किंतु अभी इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पाई है। (घोष, पी. 2018) [6]

दोनों देशों के बीच विवाद का तीसरा मुख्य बिंदु सीमा संबंधी है। गौरतलब है कि भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य बांग्लादेश से जुड़े हैं। यह सीमा पोरस बॉर्डर के रूप में जानी जाती है जिसका भारत से बांग्लादेश तक खाद्य वस्तुओं, दवाओं, मवेशियों इत्यादि की तस्करी क एक मार्ग के रूप में उपयोग किया जाता है। खासकर मवेशियों की तस्करी इस सीमा क्षेत्र में एक गंभीर समस्या है। दरअसल बांग्लादेश में गोवंश माँस की मांग बहुत अधिक है और भारत में गोवंश के वध की इजाजत नहीं है। ऐसे में तस्करों द्वारा ऐसे पशुओं की सीमा पार तस्करी का अवैध कारोबार लगातार फलता–फूलता रहता है।

भारत व बांग्लादेश के बीच हाल के कुछ वर्षों में विवाद का एक कारण बांग्लादेश व चीन के बीच बेहतर होते संबंधों से भारतीय हितों के प्रभावित होने के खतरे को लेकर भी उभरा है। ध्यातव्य है कि बांग्लादेश भारत और चीन के बीच में अवस्थति है इसलिये भारत के लिये उसका सामरिक महत्त्व बहुत ज्यादा है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने बांग्लादेश को लुक ईस्ट पॉलिसी और उसके बाद शुरू की गई एक्ट ईस्ट पॉलिसी के केंद्र में रखा है। किंतु भारत को घेरने की श्रिस्ट्रंग ऑफ पर्ल्सश् की अपनी नीति का अनुसरण करते हुए चीन बांग्लादेश को हमेशा अपने प्रभाव में लेने का प्रयास करता रहा है जिसमें एक हद तक वह सफल भी रहा है। उसको सफलता इस रूप में मिली है कि भारत द्वारा विरोध किये जाने के बाद भी बांग्लादेश चीन की महत्त्वाकांक्षी बीआरआई परियोजना से जुड़ गया। दोनों देशों के मध्य होने वाले आपसी व्यापार में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त, चीन बांग्लादेश को कई ढाँचागत परियोजनाओं को पूरा करने हेतु सस्ते ऋण के रूप में वित्तीय मदद भी मुहैया करा रहा है।

## सहयोग के क्षेत्र

यह सही है कि भारत व बांग्लादेश के संबंधों में उतार–चढ़ाव आता रहता है और दोनों के बीच कुछ विवादित मुद्दे भी अपनी जगह बनाए हुए हैं, किंतु यह भी सही है कि दोनों देश विस्तृत सहयोग के साझेदार भी हैं। यह सर्वविदित है कि बांग्लादेश के निर्माण के बाद से ही भारत ने वैश्विक मंचों पर उसके हितों की पूर्ति हेतु हमेशा उच्चस्तरीय प्रयास करते हुए बांग्लादेश विरोधी पाकिस्तानी मुहिम को कभी सफल नहीं होने दिया। दोनों देश इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, दक्षेस और बिम्सटेक जैसे समूहों में साथी सदस्य के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर आपसी सहयोग हेतु भी प्रतिबद्ध और प्रयासरत हैं। इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें दोनों देश सहयोग का गहरा नाता रखते हैं जिसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है (जहान, एस., और अख्तर, एमएफ, 2019) [8]:

- भारत द्वारा वर्ष 2011 से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) के तहत तंबाकू और शराब को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनों पर बांग्लादेश को शुल्क मुक्त कोटा प्रदान किया गया है। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करने वालों की सुगमता व लाभ के लिये दोनों देशों ने सीमाई राज्यों में बॉर्डर हाट भी स्थापित किये हैं जिनकी संख्या में वृद्धि प्रस्तावित है। इन सारे प्रयासों का लाभ यह हुआ है कि दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते उत्तरोत्तर बेहतर होते जा रहे हैं और बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। वर्ष 2018–19 में भारत ने बांग्लादेश को 9.21 बिलियन डॉलर मूल्य का निर्यात किया और 1.04 बिलियन डॉलर का आयात किया, यानी दोनों देशों का आपसी व्यापार 10 बिलियन डॉलर के आँकड़े को पार कर चुका है।
- भारत और बांग्लादेश के बीच महत्त्वपूर्ण जलमार्ग समझौते का स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार हुआ है। इसके तहत पूर्वोत्तर भारत के असम, त्रिपुरा और मेघालय जैसे राज्यों में सामान को जलमार्ग के जरिये पहुँचाया जा सकेगा। एसओपी के मुताबिक जलमार्ग, रेलमार्ग, सड़क मार्ग या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सेवा के जरिये कुल आठ मार्ग चिह्नित किये गए हैं जिनमें जलमार्ग के चार रूट शामिल हैं। पहला मार्ग चटगाँव के मंगला बंदरगाह से अखुरा होते हुए त्रिपुरा के अगरतल्ला तक का है। दूसरा, मंगला बंदरगाह से तमाबिल होते हुए मेघालय के दावकी तक का तीसरा मार्ग मंगला बंदरगाह से शिवाला होते हुए असम के सुतारकांडी तक और चौथा मार्ग मंगला बंदरगाह से बीबी बाजार के रास्ते त्रिपुरा के श्रीमंतपुर तक का है। इस समझौते के कार्यान्वयन से न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि परिवहन व्यय में भी कमी आएगी। सुखद बात यह है कि हाल ही में इस समझौते के तहत उल्लेखनीय उपलब्धि यह दर्ज हुई है कि बांग्लादेश के चटगाँव बंदरगाह से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जलमार्ग से सामान भेजकर इसका पहला सफल ट्रायल संपन्न किया गया। यह दोनों देशों के बीच मैरीटाइम कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।
- भारत और बांग्लादेश से जुड़े संयुक्त नदी आयोग, मंत्रिस्तरीय संयुक्त आर्थिक आयोग विदेश कार्यालय के स्तर पर परामर्श, गृह वाणिज्य, जल संसाधन के स्तर पर सचिव स्तरीय वार्त्ता, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल व महानिदेशक बांग्लादेश राइफल्स के स्तर पर सीमा समन्वय वार्ता, सुरक्षा पर संयुक्त कार्यदल संयुक्त सीमा कार्यदल, सीमा शुल्क अधिकारियों का संयुक्त कार्यदल और अंतर्देशीय जल परिवहन एवं व्यापार के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु स्थायी समिति आदि कुछ महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय मंच हैं जो द्विपक्षीय विषयों पर समय–समय पर वार्ता करते रहते हैं।
- बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के मध्य आपसी साझेदारी बढ़ रही है। वर्ष 2017 में बांग्लादेश भारत से लगभग 660 मेगावाट बिजली का आयात कर रहा था । इसके बाद भारतीय सार्वजनिक व निजी कंपनियों और बांग्लादेश के बीच 3600 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन, आपूर्ति व वित्तपोषण के समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कई इकाइयाँ बांग्लादेश के तेल व गैस क्षेत्र में काम कर रही हैं। भारत ने बांग्लादेश को अभी तक 8 बिलियन डॉलर की तीन लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की हैं। पहली बार वर्ष 2010 में भारत ने सार्वजनिक परिवहन, सड़कों, रेलवे, पुलों अंतर्देशीय जलमार्ग संबंधी परियोजनाओं हेतु 1 बिलियन डॉलर क्रेडिट की घोषणा की थी। इसके बाद के वर्षों में भी इस तरह की घोषणाएँ जारी रहीं । विशेष बात यह है कि जिन परियोजनाओं हेतु ये क्रेडिट प्रदान की गई उनमें अधिकांश या तो पूरी हो गई हैं या पूरी होने के कगार पर हैं।
- शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने हेतु शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय ने अपने प्रांगण में बांग्लादेश को एक ई– बांग्लादेश भवन बनाने हेतु जमीन उपलब्ध कराई है। इसके अलावा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् ने ढाका विश्वविद्यालय में टैगोर एवं हिंदी अध्ययन संस्थान की स्थापना की है।
- बांग्लादेश, भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम का एक महत्त्वपूर्ण भागीदार देश है और बांग्लादेश के विभिन्न घटकों ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का लाभ उठाया है।
- भारत व बांग्लादेश के बीच बढ़ते सहयोग का एक बड़ा प्रतिफल पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद पर काबू पाए जाने के रूप में भी देखा जा रहा है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद से ही पूर्वोत्तर विभिन्न कारणों से अशांति का शिकार बना रहा और यहाँ उग्रवाद फलता–फूलता रहा। उग्रवादी बांग्लादेश में छिपकर इस क्षेत्र में अशांति पैदा करते थे। उन्हें भारत विरोधी ताकतों द्वारा इस कार्य हेतु आवश्यक धन, हथियार व अन्य आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराई जाती थीं, किंतु जब से दोनों देशों ने उग्रवाद व आतंकवाद से साझी लड़ाई का संकल्प लिया और बांग्लादेश ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारतीय हितों के विरुद्ध कार्यों हेतु नहीं किया जा सकेगा, पूर्वोत्तर में उग्रवाद से निपटने में भारत को उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है।
- भारत का इंदिरा गांधी संस्कृतिक केंद्र, बांग्लादेश में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है। यह परिषद नियमित रूप से बांग्लादेश में सांस्कृतिक गतिविधियों वाले कार्यक्रम आयोजित करती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त, यह परिषद योग, हिंदी भाषा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, मणिपुरी नृत्य, कथक और चित्रकारी में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करती है। इस तरह के कार्यक्रम बांग्लादेशी विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय हैं।

## निष्कर्ष

भारत को यह भलीभाँति पता है कि दक्षिण एशिया एवं दक्षिण–पूर्व एशिया का भू–राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर है और इस क्षेत्र में चीन भारत को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंधों की स्थापना हेतु भारत को लगातार प्रयासरत रहना होगा। खासकर बांग्लादेश जैसा देश जो कि दक्षिण एशिया में भारत के

बाद दूसरे बड़े ताकतवर देश के रूप में उभरा है और जो भारत व चीन के बीच में अवस्थित है, के साथ अच्छे संबंध भारत के सामरिक हितों की पूर्ति हेतु आवश्यक हैं। सुखद तथ्य यह है कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बेहद अच्छे हैं तथा उन्हें और अच्छा बनाने के हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं।

## संदर्भ सूची


1. चौधरी, जीडब्ल्यू. भारत–बांग्लादेश संबंधः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उभरते रुझान, एशियाई मामले,2019:50(3):248–2631
2. खान, एमएम. भारत–बांग्लादेश संबंधः अवसर और चुनौतियाँ, भारत त्रैमासिक,2018:74(4):331–3461
3. साहा, आर. भारत–बांग्लादेश संबंधः एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जर्नल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स,2020:2(1):27–391
4. कुमार, आर. भारत–बांग्लादेश संबंधः एक सिंहावलोकन, सामरिक विश्लेषण,2017:41(5):434–4401
5. अकबर, एमएस. भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक संबंधः चुनौतियाँ और अवसर, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन,2019:56(3):238–2511.
6. घोष, पी. भारत–बांग्लादेश संबंधः सुरक्षा मुद्दों पर फोकस, जर्नल ऑफ कंटेम्परेरी ईस्टर्न एशिया,2018:17(2):29–451
7. दत्ता, एस. भारत–बांग्लादेश संबंधः अतीत, वर्तमान और भविष्य, भारत त्रैमासिक,2017:73(2):159–1761
8. जहान, एस., और अख्तर, एमएफ. भारत–बांग्लादेश से सहयोग और संघर्ष की गतिशीलता, एशियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस,2019:27(3):265–2821
9. पॉल, एम., और खान, एमएच. जल बंटवारा और भारत– बांग्लादेश संबंधः संभावनाएँ और चुनौतियाँ, जर्नल ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज,2020:55(8):1192–1208
10. बिस्वास, एस, और साहा, एस. सीमा प्रबंधन और भारत– पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, बांग्लादेश संबंधः चुनौतियाँ और संभावनाएँ, इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन,2018:(12)1:83–97
11. चौधरी, एआर. भारत–बांग्लादेश संबंधः क्षेत्रीय स्थिरता के लिए निहितार्थ, दक्षिण एशियाई सर्वेक्षण,2019:26(1):95–1101